

संविधान की शक्ति राज्यपाल को 5 विधायक और राज्यपाल को अधिकार
 दिए जाते हैं विधायकों की संख्या 57 से अधिक है। उनमें 25 प्रति
 हैं - आपराधिक आरोप प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया, विकास एवं समाज
 उत्थरण तथा निराश्रित तथा परिवार नियंत्रण, विधायक, उच्च अदालत
 आदि एवं समाजिक योजना, सेवा, परामर्श प्रदाता, सेवा आदि।

उन विधायकों पर राज्यों एवं राज्यपालों को विचार
 बनाने का अधिकार है। किन्तु यदि राज्यपालों व संसदीय विधायकों में
 एक ही चीज है तो संसदीय विधि प्रभावी होगी, यदि एक विधि को
 राज्यपालों की शक्ति मिली तो राज्य में राज्यपाल ही प्रवर्तित
 रहेगी।

केन्द्र-राज्य प्रशासनिक संबंध

संविधान के भाग 71 में अनुच्छेद 252 से 263 तक
 केन्द्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। केन्द्र (राज्यपालों
 में प्रशासनिक संबंधों का संशोधन करते करिब करते हैं। संविधान
 के अनुच्छेद 73 के अंतर्गत राज्य की प्रशासनिक अधिकार उन विधायकों
 पर सीमित है जिन पर राज्यपालों को विधिक निर्णय के अधिकार
 हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्यों की प्रशासनिक
 अधिकारों उन विधायकों पर सीमित है जिन पर राज्यपालों को
 का विचार का अधिकार है। एकात्मिक राज्य के विधान पर
 संसदीय प्रशासनिक अधिकार राज्यों में निर्दिष्ट हैं कि उन
 विधायकों पर राज्य की प्रशासनिक अधिकार कुछ विशेष परिस्थितियों
 में राज्य के प्रशासनिक अधिकार के अंतर्गत हैं जहाँ राज्यपालों द्वारा
 प्रावधान किया गया है। ये उपरोक्त हैं -

* * संविधान के अनुच्छेद 257 के अंतर्गत राज्यपाल यह अधिकार
 हैं कि अपनी कार्यपालिका अधिकार प्रयोग कर राज्यपालों को जिनसे
 संसद के अंतर्गत आ अनुपालन सुनिश्चित हो तथा केन्द्रिय
 प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

* संविधान के अनुच्छेद केन्द्र (राज्यों की निम्नलिखित मामलों में
 निर्देश दे सकता है -

- (i) संसद के अधिनो की बनाये रखें एवं उनका रख-रखाव को।
- (ii) राज्य सेलवे व्यय को भी रखा करे।
- (iii) प्रशासनिक विभाग के अधिकारों मध्य संसदीय वरुणों के अंतर्गत
 मामलापन सीमित की व्यवस्था करे।
- (iv) राज्य में अनुसूचित जातियों के अत्याज से अलग विधायक
 योगदान बनाने और उनका नियंत्रण करे।

* राज्यपालों राज्यों की सरकारों को राज्यपालों में वर्णित विधायकों
 को संसदीय कार्य कार्य बाँध सकता है।

* संविधान में यह प्रावधान है कि केन्द्र-राज्य सरकारों का
 संबंध है कि वे अपनी सरकारी कृत्यों का आधार को और

देहा से टूटती न्यायालयों द्वारा विधेयों में अंतिम निर्णयों से लाय
है।

- * संविधान संशय तथा राज्यों की प्रकृत लोकसेवाओं के अतिरिक्त
अतिरिक्त भारतीय सेवाओं में भाग लेना चाहते हैं। इन सेवाओं से लाभान्ना
का अधिकार संशय की है। इन सेवाओं से यह लाभ राज्यों के उत्पन्न है।
पर भारतीय सेवाओं लोकिक अर्थ की राज्यों पर निर्भरता कम कर
करते।
- * राज्यालय का पर भी राज्यों पर केन्द्रीय निर्भरता की अतिरिक्त
राज्यपाल की विधुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल
राज्य की संवैधानिक प्रकृति होने से स्वयं-स्वयं राज्य के केन्द्र का
लेने पर भी होकर है।
- * संवैधानिक संस्थाओं के अर्थ अतिरिक्त प्रकृत अर्थों कि वह
किसी अन्तर्जातीय नदी से पानी का प्रयोग विज्ञान और निर्भरता के
संबंध में किसी निवारण या विचार पर डालना निर्णय दे सकते हैं।
- * संविधान राष्ट्रपति को अतिरिक्त प्रकृत अर्थों (अनुच्छेद 263) कि
वह केन्द्र-राज्यों के अर्थ का अर्थिक प्रकृत के विषयों की जाते वह
वह के अर्थिक अन्तर्जातीय प्रकृत का अर्थिक अर्थिक अर्थिक। वह
तरह की प्रकृत का अर्थिक 1990 में किया गया था।
- * राज्यों पर केन्द्र के अन्तर्जातीय निर्भरता प्रकृत वह प्रकृत
अनुच्छेद 265 है। प्रकृत अनुच्छेद के अन्तर्गत अर्थिक अर्थिक
केन्द्र की निर्देशों का प्रकृत अर्थिक के निकल रहे हैं जो
वैश्वपति को प्रकृत अर्थिक है कि अर्थिक में संवैधानिक अर्थिक
निकल से प्रकृत है जो अर्थिक में अर्थिक अर्थिक अर्थिक है
जाते हैं।

2 केन्द्र-राज्य विधीय संबंध

संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 265 है
213 वह केन्द्र-राज्य विधीय संबंधों का निर्णय है। संवैधानिक
अर्थिक में विधीय तथा अर्थिक अर्थिक अर्थिक के अर्थिक-अर्थिक
विधीय अर्थिक का अर्थिक एवं अर्थिक में अर्थिक एवं अर्थिक अर्थिक
विधीय में अर्थिक का अर्थिक अर्थिक है। संविधान के अर्थिक केन्द्र
और अर्थिक के अर्थिक विधीय संबंधों का निर्णय अर्थिक
किया गया है -

- (i) अर्थिक अर्थिक तथा अर्थिक अर्थिक का अर्थिक अर्थिक
- (ii) अर्थिक अर्थिक तथा अर्थिक अर्थिक अर्थिक अर्थिक अर्थिक अर्थिक
- (iii) अर्थिक अर्थिक अर्थिक अर्थिक अर्थिक
- (iv) अर्थिक अर्थिक अर्थिक अर्थिक अर्थिक
- (v) अर्थिक अर्थिक अर्थिक अर्थिक अर्थिक
- (vi) अर्थिक अर्थिक अर्थिक अर्थिक अर्थिक अर्थिक अर्थिक अर्थिक।

निवर्तन: विद्यापीठ, प्रशासनिक और विधीय क्षेत्र में केन्द्र-राज्य
 संबंधों के सुदृढ़ बनाने के लिए है। विद्यमान समस्त
 कानूनों में केन्द्रीय सरकार के राज्यों पर निर्धारण की
 शक्ति प्रदान की गई है। केन्द्रीय सरकार (राज्य सरकारों
 की अपेक्षा उच्चतर क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली है। केन्द्र
 शासन में एम.जी. पायल की अध्यक्षता है कि, "वर्तमान स्थिति में
 राज्यों के पास सीमित शक्ति है और अपनी परिभाषित विषय
 क्षेत्रों को छोड़कर उन्हें केन्द्र की सरकारों की शक्ति
 का हस्तान्तरण है इसलिए उन्हें केन्द्र का नेतृत्व स्वीकार करना
 पड़ता है। कभी-कभी केन्द्र को राज्यों के साथ मुझना भी
 पड़ता है।

GIRISH K SINHA, Asst. Professor
 Dept: POLSC.
 RIN College, Ranchi, Jharkhand
 class - Deg II (H), Paper - III
 Topics: Centre-State Relations
 Date: